



दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 03 जनवरी 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए || वर्ष-02, अंक- 96

महत्वपूर्ण एवं खास

केरल सरकार को सीएए हटाने का प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं: राज्यपाल

तिरुवनंतपुरम्



(आरएनएस)। केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को हटाने के लिए पास हुए प्रस्ताव को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गलत कराया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि किसी राज्य को केंद्रीय विषयों पर प्रस्ताव पास करने का अधिकार ही नहीं है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, नागरिकता का मामला केंद्र सरकार का विषय है, इसको लेकर राज्य सरकार के प्रस्ताव पारित करने का कहीं कोई संवैधानिक आवार नहीं है। मुख्यमंत्री पिण्डराई विजयवन ने मंगलवार को विधानसभा में सीएए हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था जिसे बाद में विधानसभा ने पारित किया था। इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने समर्थन किया था वहीं भारतीय जनता पार्टी (भजप) ने कड़ा एतराज जताया। प्रस्ताव पास करने के पीछे मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा था कि केरल में सेवयुलरिज़ (धर्म निरपेक्षता) का सुनहरा इतिहास रहा है। ऐसे में इस प्रस्ताव को बनाए रखने के लिए ऐसे कानून का विरोध जरूरी है।

एनसीपी के कदाचर नेता डीपी त्रिपाठी का दिल्ली में निधन

» लंबे समय से थे बीमार नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रादी कांग्रेस पार्टी नेता और पूर्व सांसद डीपी त्रिपाठी का गुरुवार को निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। डीपी

त्रिपाठी का जन्म यूपी के सुल्तनपुर में हुआ था। वह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक यारी की शुरूआत कांग्रेस से की थी, लेकिन बाद में उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर लिया था। सुप्रिया सुले ने डीपी त्रिपाठी के निधन पर ट्वीट कर शक्ति किया है। उन्होंने लिखा कि डीपी त्रिपाठी के निधन के बारे में सुनकर गर्जा दुःख हुआ। वे एनसीपी के महासचिव थे, हम सभी के मार्गदर्शक और संरक्षक थे। हम उनके परामर्श और मार्गदर्शन को याद करेंगे, जो उन्होंने उस दिन से दिया था, जिस दिन एनसीपी की स्थापना हुई थी। उनकी आत्मा को शांति मिले।

मेट्रो से सफर करने वालों को मिलेगी वाई-फाई सुविधा

» दिल्ली को नए साल का तोहफा

नईदिल्ली, 02 जनवरी (आरएनएस)। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर अब वाई-फाई की सुविधा शुरू होने जा रही है। अब तक कुछ मेट्रो स्टेशनों पर ही वाई-फाई की सुविधा है। वह देश में वहली ऐसी मेट्रो होगी, जिसमें पैसेंजर्स को वाई-फाई की सुविधा मिलेगी। दिल्ली मेट्रो के सूर्यों का कहना है कि गुरुवार को वह सुविधा शुरू हो सकती है। फिल्हाल मेट्रो पैसेंजर्स को फी वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी।

यूएस में कलाइबिंग के दौरान 150 मोटर नीचे गिरा भारतीय मूल का युवक, बाल-बाल बची जान

ओटाओ। कनाडा में रहने वाले एक भारतीय मूल का युवक अपरिकी राज्य ऑरेन में मार्ट छोड़ नामक पहाड़ी पर कलाइबिंग के दौरान 150 मोटर नीचे गिर गया, जिसे बचाव दल की ओर से कड़ी मशक्त के बाद बचाया जा सका। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 16 साल का गुरुवार रात सिंह गत साप्ताह को अपने दोस्तों के साथ कलाइबिंग कर रहा था। इस दौरान वह अचानक बर्फ पर अना संतुलन खो बैठा और फिलकर नीचे गिर गया।

इंडोनेशिया की राजधानी में बाढ़ आने से 23 लोगों की मौत, कई फंसे जाकर। इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता में भीषण बाढ़ और भूस्खलनों के कारण कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई। इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बहस्तिवार को कहा कि मृतक संख्या और बढ़ने की आशंका है। प्रभावित इलाके में कर्मी तीन करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ से हजारों लोगों को अस्थायी शरणस्थलों पर भेजा गया।

सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को मिला कृषि कर्मण पुरस्कार

छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया।

कृषि मंत्री वीरोद्ध चौबे ने राज्य की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन प्रेरणा-2 के अंतर्गत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए भारत सरकार के प्रदेश के अवलोकित किसानों के नाम समर्पित किया है। उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार के लिए चुना गया है कृषि मंत्री



रवीन्द्र चौबे ने प्रदेश के किसानों और विभागीय अधिकारियों को इस उत्पादनिक के लिए बधाई दी है। कृषि मंत्री चौबे ने इस पुरस्कार के लिए विभागीय अधिकारियों को बधाई दी है। पुरस्कार के रूप में पांच करोड़ रुपए की राशि, ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। कृषि मंत्री के साथ संचालक कृषि टामन सिंह सोनवानी, अपर संचालक एस.एस. केरकेट्टा और संचालक समेती डी.के. भोयर ने पुरस्कार ग्रहण किया।

भारतीय रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नम्बर '139'

नईदिल्ली (आरएनएस)। रेल से सफर के दौरान पूछताछ एवं शिकायत निवारण के लिए कई हेल्पलाइन नम्बर रहने के कारण यात्रियों को हो रही असुविधा को समाप्त करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक अभियान शुरू किया है।

भारतीय रेलवे ने इसके तहत समस्त हेल्पलाइन नम्बरों को एकीकृत कर केवल एक हेल्पलाइन नम्बर '139' में तब्दील कर दिया है, ताकि सफर के दौरान यात्रियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों का त्वरित निवारण संभव हो सके। सभी मौजूदा हेल्पलाइन नम्बरों (182 को छोड़कर) के स्थान पर अब केवल एक ही नया हेल्पलाइन आसान हो जाएगा।



नम्बर '139' रहने से यात्रियों के लिए इस नम्बर को याद रखना और सफर के दौरान अपनी सभी जस्तरों की पूर्ति के लिए रेलवे से संपर्क साधना या केवल करना काफ़ी आसान हो जाएगा।

हेल्पलाइन नम्बर '139' वार्षिक आरएस (इंटरएक्टिव वॉयस रिसॉन्स सिस्टम) पर आधारित है। हेल्पलाइन नम्बर '139' पर कॉल करने के लिए किसी स्मार्ट फोन की जरूरत नहीं है। अतः ऐसे में सभी मोबाइल यूजर के लिए इस नम्बर तक आसान पहुंच रहेगी।



चौदह वैज्ञानिकों को स्वर्ण गणतंत्र दिवस परेड में नहीं दिखेगी पश्चिम बंगाल की झांकी

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार द्वारा 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी को शामिल नहीं किया गया है।

फेलोशिप और शोध के लिए चुने गए वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रैद्योगिकी के विभाग द्वारा शोध कार्यों के लिए मदद के साथ ही 25,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप शामिल है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को उनके वेतन के अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए 5 लाख रुपये का शोध अनुदान भी दिया जाता है। कुल 443 आवेदकों में से, 14 वैज्ञानिकों को इस बार फेलोशिप के लिए चुना गया है।

राज्य कार्यालय ने बुधवार को जानकारी दी कि बंगाल सरकार की झांकी का प्रस्ताव विशेषज्ञ समिति के पास दो बार भेजा गया। दूसरी बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद इसे खारिज कर दिया गया। मंत्रालय के मुताबिक, बंगाल की झांकी को पहले घेरे बैठक की छह प्रतिक्रियाएँ से दोनों सरकारों के बीच टकराव बढ़ सकता है। 2018 में भी बंगाल की झांकी को शामिल नहीं की गई थी और उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था।

» केंद्र ने दुकराया ममता सरकार का प्रस्ताव

था। 2020 में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 56 झांकियों के प्रस्ताव आए थे। इन झांकियों के चुनाव के लिए विशेषज्ञ समिति में पांच दौर की बैठक की।

प्रस्ताव अंतिम रूप से गणतंत्र दिवस परेड 2020 के लिए चुने गया है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से झांकियों के 32 और केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों से 24 प्रस्ताव मिले थे।

झांकियों का चयन एक विशेष समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला और नृत्यकला से शामिल नहीं की गई थी और उसके प्रस्तावों पर खारिज कर दिया गया था। यह समिति प्रस्तावों पर लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्रस्ताव आर्यत्रित किए जाते हैं। झांकियों का चयन एक विशेष शामिल नामी जाए जाने से दोनों सरकारों के बीच टकराव बढ़ सकता है। 2018 में भी बंगाल की झांकी को शामिल नहीं की गई थी और उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया